हिन्दी दैनिक

लखनऊ जंक्शन

RNI NO.-UPHIN/2015/64743 Email-lkojunction@gmail.com

वर्ष: 11 अंक: 134 लखनऊ, रविवार 04 जनवरी 2026 पृष्ठ: 04 मूल्य: 01 रूपये

संक्षिप्त समाचार

गिग व्यवस्था से डिलीवरी कर्मियों पर दबाव नहीं : गोयल

एजेंसी

नयी दिल्ली। गिग कर्मचारियों की कमाई और कामकाजी परिस्थितियों को लेकर जारी बहस के बीच एटरनल के संस्थापक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी दीपिंदर गोयल ने कहा कि यह व्यवस्था डिलीवरी करने वाले कर्मियों पर दबाव नहीं डालती तथा लचीले कार्य घंटे और कल्याणकारी सुविधाएं गिग कार्य को अनेक लोगों के लिए आय का भरोसेमंद साधन बनाती हैं। एटर्नल के पास खाद्य आपूर्ति कंपनी जोमैटो और क्विक–कॉमर्स फर्म ब्लिंकिट का स्वामित्व है। गोयल की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब गिग कर्मियों के संगठन बेहतर भुगतान और कार्य परिस्थितियों की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। गोयल ने सामाजिक माध्यम 'एक्स पर लिखा, वर्ष 2025 में जोमैटो और ब्लिंकिट ने डिलीवरी करने वाले सहयोगियों के लिए बीमा सुरक्षा पर 100 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए।

योगी सरकार के "साइबर कमांडो" साइबर अपराधियों का काम करेंगे तमाम

– एसपीजी और एनएसजी कमांडो की तर्ज पर तैयार किये गये साइबर कमांडो

– आईआईटी कानपुर, नया रायपुर, मद्रास, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू) के एक्सपर्ट से ली ट्रेनिंग

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। योगी सरकार ने साइबर अपराधियों की कमर तोड़ने और साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए "साइबर कमांडो" की एक विशेष टीम तैयार की है। इन कमांडो को एसपीजी और एनएसजी कमांडो की तर्ज पर देश के विभिन्न उच्च संस्थानों के एक्सपर्ट द्वारा साइबर अपराध और ठगी को रोकने के लिए ट्रेनिंग दी गयी है। जिस तरह से एनएसजी और एसपीजी कमांडो अपने कार्य क्षेत्र में दक्ष होते हैं, यही भी ठीक उसी तरह अपने कार्य क्षेत्र में दक्ष (साइबर अपराध को रोकने) हैं। इसके साथ ही साइबर कमांडो को हाईटेक टेक्नोलॉजी और टूल्स से लैस किया गया है ताकि साइबर ठगों के नेक्सेज को पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया जा सके।

आईआईटी कानपुर, नया रायपुर, मद्रास और आरआरयू के एक्सपर्ट से ली ट्रेनिंग

साइबर/ सीआईडी डीजी बिनोद

कुमार सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में साइबर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिये थे। ऐसे में मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरुप अत्याधुनिक तकनीक से लैस करते हुए 'साइबर कमांडो' की विशेष टीम तैयार की गई है। इस टीम में कुल 15 पुलिसकर्मी शामिल हैं। ये साइबर कमांडो न केवल साइबर ठगी और डिजिटल अपराधों पर लगाम लगाएंगे, बल्कि आम नागरिकों को सुरक्षित डिजिटल वातावरण उपलब्ध कराने में भी अहम भूमिका निभाएंगे। इन साइबर कमांडो की संरचना और प्रशिक्षण एसपीजी और एनएसजी कमांडो की तर्ज पर दिया गया है। जिस तरह देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए विशेष बल कार्य करते हैं, उसी प्रकार साइबर कमांडो डिजिटल दुनिया में अपराधियों के खिलाफ मोर्चा संभालेंगे। उन्होंने बताया कि इन 15 साइबर कमांडो को तैयार करने में देश के प्रतिष्ठित तकनीकी और सुरक्षा संस्थानों की विशेषज्ञता ली गई है। इन्हे आईआईटी कानपुर, नया रायपुर, मद्रास और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू), गुजरात के विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी (एनएफएसयू), गुजरात और नई दिल्ली से साइबर फॉरेंसिक, डिजिटल ट्रेसिंग और ऑनलाइन अपराध की जांच से जुड़ी आधुनिक तकनीकों की ट्रेनिंग ली गई।

साइबर कमांडो जिला और थाने स्तर के पुलिसकर्मियों को दे रहे प्रशिक्षण

साइबर/ सीआईडी डीजी ने बताया कि पहले चरण में 15 चयनित पुलिस कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। ये सभी तकनीकी दक्षता, विश्लेषण क्षमता और फील्ड अनुभव के आधार पर चुने गए हैं। यह कमांडो आने वाले समय में अन्य पुलिसकर्मियों को भी प्रशिक्षित करेंगे, जिससे प्रदेश भर में साइबर अपराध से निपटने की क्षमता कई गुना बढ़ेगी। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद साइबर कमांडो को पुलिस जोन और मुख्यालय स्तर पर तैनात किया गया है। इसका उद्देश्य साइबर अपराध की सूचना मिलते ही त्वरित और तकनीकी रूप से सक्षम कार्रवाई की जा सके। ये कमांडो साइबर ठगी, ऑनलाइन फ्रॉड, ऑनलाइन साइबर हमलों, सोशल मीडिया अपराध, डाटा चोरी, फिशिंग और डिजिटल ब्लैकमेलिंग जैसे मामलों में विशेष भूमिका निभाएंगे। इसके साथ ही साइबर कमांडो जिला और थाने स्तर के पुलिसकर्मियों को भी तकनीकी प्रशिक्षण दे रहे हैं, ताकि जमीनी स्तर पर भी साइबर अपराधों की पहचान और जांच बेहतर ढंग से हो सके।

एडवांस्ड सॉफ्टवेयर, डिजिटल फॉरेंसिक टूल्स आदि से कमांडो लैस

योगी सरकार ने साइबर कमांडो को हाईटेक उपकरण भी उपलब्ध कराए हैं, जिनमें एडवांस्ड सॉफ्टवेयर, डिजिटल फॉरेंसिक टूल्स, डाटा एनालिटिक्स सिस्टम और रियल–टाइम मॉनिटरिंग तकनीक शामिल है। इन उपकरणों की मदद से साइबर अपराधियों के डिजिटल फुटप्रिंट को ट्रैक करना, लेन–देन का विश्लेषण करना और अपराध के नेटवर्क तक पहुंचना आसान होगा। योगी सरकार का मानना है कि कानून–व्यवस्था केवल पारंपरिक अपराधों तक सीमित नहीं रह गई है। आज अपराधी डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर आम जनता को निशाना बना रहे हैं। ऐसे में पुलिस को तकनीकी रूप से सशक्त बनाना समय की आवश्यकता है। इसी को देखते हुए साइबर कमांडो नियुक्त किये गये हैं।

पौष पूर्णिमा स्नान पर्व के साथ माघ मेला का भव्य शुभारंभ

कड़ाके की ठंड के बाद भी संगम में उमड़ा आस्था का सैलाब, प्रथम स्नान पर्व पर 31 लाख से अधिक ने किया पुण्य स्नान कल्पवासियों ने लिया जप–तप और संयम का संकल्प, संत, महात्मा और दूरदराज से आए श्रध्दालुओं ने लगाई श्रध्दा की डुबकी मेला क्षेत्र में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम, ब्रह्म मुहूर्त से ही स्नान घाटों पर मुस्तैद और चौकन्ना रहा प्रशासन

बीएनई

प्रयागराज। देश के सबसे विशाल, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक वार्षिक समागम माघ मेला–2026 का शनिवार को तीर्थराज प्रयागराज में शुभारंभ हो गया। संगम और उसके आसपास के सभी घाटों पर पौष पूर्णिमा स्नान पर्व पर भोर से ही पवित्र स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रशासन की तरफ से की गई व्यवस्था से श्रद्धालु भी गदगद दिखे। ठंड हवाओं और गलन के बाद भी श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं नजर आई। सायं सात बजे तक लगभग 31 लाख लोग संगम में स्नान कर चुके थे। यह संख्या 35 लाख तक पार कर लिए जाने का अनुमान है।

त्रिवेणी तट पर उमड़ा आस्था सैलाब, आध्यात्मिक उल्लास और धार्मिक आस्था मेल

पौष पूर्णिमा के अवसर पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पवित्र संगम व विभिन्न घाटों पर दिन भर स्नान का क्रम चला। संगम तट पर आध्यात्मिक उल्लास और धार्मिक आस्था का अद्वितीय मेल दिखा। देश भर के कोने–कोने से आए श्रद्धालुओं के लिए माघ मेले में पौष पूर्णिमा स्नान पर्व का दिव्य स्नान

जीवन का अद्वितीय अनुभव बन गया है। हरियाणा की रेवाड़ी से आई निशा का कहना है कि त्रिवेणी के पावन जल में पुण्य की डुबकी से जीवन धन्य हो गया। सरकार ने मेला क्षेत्र में आने–जाने से लेकर घाटों में स्नान की उत्तम व्यवस्था की है। अपने पूरे परिवार के साथ मध्य प्रदेश के सीहोर से त्रिवेणी स्नान के लिए आई कल्पना तोमर का कहना था कि महाकुंभ में त्रिवेणी स्नान की जो कामना अधूरी रह गई थी, इस बार पूर्ण हो गई। मेला क्षेत्र में स्वच्छता और व्यवस्था सराहनीय है। सनातन आस्था से जुड़े विभिन्न संत सम्प्रदाय के संत महात्माओं ने भी त्रिवेणी के पावन जल में माघ मेला की पहली डुबकी लगाई।

उत्सव और उल्लास की बयार, मुस्तैद दिखा प्रशासन

माघ मेला के आरंभ के साथ ही संपूर्ण मेला क्षेत्र में उत्सव और उल्लास की बयार प्रवाहित हो रही है। कमिश्नर प्रयागराज सौम्या का कहना है कि शाम सात बजे तक 31 लाख से अधिक से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में पुण्य स्नान कर लिया था। यह सिलसिला अभी भी जारी है। स्नान के मुहूर्त के समापन तक यह आंकड़ा 35 लाख तक पार कर जाने का अनुमान है। माघ मेला में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर व्यापक और मजबूत सुरक्षा इंतज़ाम किए गए। मेला पुलिस अधीक्षक नीरज पांडेय का कहना है कि शहर और मेला क्षेत्र में 1500 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से चौबीसों घंटे केंद्रीय कमांड सेंटर से निगरानी की जा रही है। वहीं आधुनिक उपकरणों से लैस सुरक्षाकर्मी प्रभावी भीड़ प्रबंधन में जुटे हैं। घाटों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम, वॉच टावर और जल पुलिस की सक्रिय पेट्रोलिंग से श्रद्धालुओं को सुचारु और सुव्यवस्थित सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

कल्पवासियों ने लिया संकल्प, जीवंत हुई तंबुओं की नगरी

हर साल माघ के महीने मोक्ष दायिनी मां गंगा के तट पर शुरू होने वाली धार्मिक परम्परा कल्पवास का भी इसी प्रथम स्नान पर्व के साथ आरंभ हो गया। मेला क्षेत्र में पहली बार कल्पवासियों के लिए बनाया गया प्रयागवाल नगर भी इसी के साथ जीवंत हो उठा। पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक चलने वाले कल्पवास का पहला स्नान आज था। मेला क्षेत्र में कल्पवास करने आए 4 लाख से अधिक कल्पवासियों ने गंगा स्नान कर आज से कल्पवास का संकल्प लिया।

काशी में आज होगा वॉलीबॉल 'महाकुंभ' का उद्घाटन

-प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 12 बजे करेंगे वर्चुअली उद्घाटन, 11 जनवरी तक चलेगा मुकाबला

-मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टेडियम में उपस्थित हो खिलाड़ियों का बढ़ाएंगे उत्साह

बीएनई

वाराणसी। 72 वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चौंपियनशिप का उद्घाटन 4 जनवरी को काशी के सिगरा स्टेडियम में होगा। वाराणसी के सांसद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वर्चुअली इस प्रतियोगिता का उद्घाटन 12 बजे करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टेडियम में मौजूद रहकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाएंगे। उद्घाटन समारोह में उत्तर प्रदेश वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष व उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। सिगरा स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में यह प्रतियोगिता 11 जनवरी तक चलेगी। इसमें देश भर से 58 टीमें (पुरुष एवं महिला) भाग ले रही है। चौम्पियनशिप में स्विट्जरलैंड से अंतरराष्ट्रीय वॉलीबॉल महासंघ के आब्जर्वर भी मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश वॉलीबॉल संघ के सचिव सुनील कुमार तिवारी ने बताया कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पहली बार सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चौंपियनशिप हो रही है। इसमें 30 पुरुष और 28 महिला टीमें भाग लेंगीं। जिला वॉलीबॉल संघ के अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह ने बताया कि रेलवे के अलावा सेना के तीनों अंगों (जल,थल, नभ) को मिलाकर बनी टीम भी प्रतिभाग करेगी। प्रतियोगिता 11 जनवरी को समाप्त होगी। उन्होंने जानकारीदी कि उत्तर प्रदेश में कई वर्षो (1984) के बाद ये चौंपियनशिप होनी जा रहा है। पूर्वांचल के खेल प्रेमियों के लिए ये चौम्पियनशिप बहुत बड़ा आयोजन है। इसमें से सेलेक्ट किये हुए खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। आयोजन समिति के अध्यक्ष और वाराणसी के मेयर अशोक तिवारी ने बताया कि साई और खेल विभाग उत्तर प्रदेश के बीच सिगरा स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सेण्टर ऑफ़ एक्सिलेन्स के बीच एमओयू होना है। आयोजन समिति की ओर से खेल का शुभांकर (नंदी और डॉलफिन) भी जारी किया जा चूका है 72 वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चौंपियनशिप में देश भर के लगभग 1044 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे,जिसमें 540 पुरुष खिलाड़ी और 504 महिला खिलाड़ी हैं। राष्ट्रीय स्तर के इस उद्घाटन समारोह में सभी खेलो के राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ ही पद्मश्री सम्मान से सम्मानित और गणमान्य लोगो को भी आमंत्रित किया गया है। आयोजन समिति के अध्यक्ष और

महापौर अशोक तिवारी ने कहा कि यह आयोजन केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि काशी को 'स्पोर्ट्स टूरिज्म हब' के रूप में स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने विश्वास जताया कि काशी की यह मेजबानी आने वाले वर्षों में और बड़े अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों का मार्ग प्रशस्त करेगी।

उन्नाव रेप केस : कुलदीप सेंगर की बेटी ने अमित शाह को लिखी चिट्ठी

कहा– हमें मिले स्थायी सुरक्षा... अनहोनी का जताया डर

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। उन्नाव बलात्कार मामले में उम्रक़ैद की सजा काट रहे पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सेंगर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक भावुक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने पीड़िता और उसके परिवार को निरंतर सुरक्षा प्रदान करने की गुहार लगाई है, ताकि किसी अप्रिय घटना पर उनके पिता पर फिर से आरोप न लगे। ऐश्वर्या ने पत्र में चिंता व्यक्त की कि पीड़िता सोशल मीडिया और मीडिया पर बार–बार बयान दे रही है कि यदि कुलदीप सेंगर को जमानत या रिहाई मिली तो वह या उनका परिवार आत्महत्या कर लेगा। ऐश्वर्या का कहना है कि ऐसे बयानों से डर का माहौल बन रहा है और अगर पीड़िता पक्ष के साथ कोई हादसा हुआ तो सारा ठीकरा उनके पिता के सिर फोड़ा जाएगा। पत्र में पुरानी घटनाओं का हवाला देते हुए ऐश्वर्या ने याद दिलाया कि 2018 में पीड़िता ने मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह की कोशिश की थी, जिसके बाद मीडिया दबाव में उनके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं, 2019 की सड़क दुर्घटना में पीड़िता घायल हुई और उनके रिश्तेदारों की मौत हुई, लेकिन सीबीआई, आईआईटी दिल्ली, सीएफएसएल और सीआरआरआई की जांच में इसे स्पष्ट दुर्घटना माना गया। दिल्ली कोर्ट ने इस मामले में सेंगर को बरी कर दिया और कोई अपील नहीं हुई, फिर भी मीडिया में हत्या के प्रयास का आरोप लगाया जाता रहा। ऐश्वर्या ने मीडिया पर पक्षपातपूर्ण कवरेज का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे निष्पक्ष ट्रायल का हक छिन गया और हर राहत वाले फैसले पर विरोध शुरू हो जाता है।

छत्तीसगढ़ में सुरक्षा कर्मियों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 12 से अधिक नक्सली मारे गए

एजेंसी

सुकमा/बीजापुर। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में सुरक्षाबलों के साथ शनिवार को दो अलग–अलग मुठभेड़ों में 12 से अधिक नक्सली मारे गए। पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षाबलों ने सुकमा जिले में 10 से ज्यादा नक्सलियों को तथा पड़ोसी बीजापुर जिले में दो अन्य नक्सलियों को मार गिराया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुकमा जिले में दक्षिणी क्षेत्र के जंगल में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। उन्होंने कहा, अब तक 10 से अधिक नक्सलियों को मार गिराया गया है। अभियान अब भी जारी है। इस संबंध में विस्तार से जानकारी बाद में दी जाएगी। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि बीजापुर जिले के दक्षिणी क्षेत्र में सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में दो नक्सलियों को मार गिराया। उन्होंने बताया कि बीजापुर जिले के दक्षिणी क्षेत्र में नक्सलियों के बीच शनिवार सुबह पांच बजे से रुक–रुक कर मुठभेड़ जारी है। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ स्थल से अब तक दो नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि अभियान अब भी जारी है इसलिए मुठभेड़ के स्थान, अभियान में शामिल सुरक्षाबलों की संख्या तथा अन्य संवेदनशील जानकारी इस समय साझा नहीं की जा सकती ताकि

अभियान में शामिल जवानों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने बताया कि अभियान पूरा होने के बाद विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी। पिछले वर्ष सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में 285 नक्सलियों को मार गिराया था।

दिल्ली लालकिला विस्फोट केस, पटियाला हाउस कोर्ट ने डॉ मल्ला को 16 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा

दिल्ली ब्यूरो

नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने 10 नवंबर को लालकिले के पास हुए विस्फोट मामले के आरोपियों में

से एक डॉ. बिलाल नसीर मल्ला को 16 जनवरी तक 13 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने शनिवार को मल्ला को कड़ी सुरक्षा के बीच पटियाला हाउस अदालत में पेश किया। मल्ला को 26 दिसंबर को आठ दिन के लिए एनआईए की हिरासत में भेजा गया था और एजेंसी ने उसकी हिरासत अवधि समाप्त होने पर उसे अदालत में पेश किया। मीडियाकर्मियों को कार्यवाही कवर करने से रोक दिया गया था। आरोपी को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने मल्ला को 16 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। एनआईए ने नौ दिसंबर को मल्ला को दिल्ली में गिरफ्तार किया था और उसे साजिश का मुख्य आरोपी बताया था। एनआईए की जांच के अनुसार, मल्ला ने जानबूझकर डॉ. उमर–उन–नबी को रसद संबंधी सहायता प्रदान की थी। नबी आत्मघाती हमलावर था, जो वह विस्फोटक से भरी आई20 कार चला रहा था जिसमें 10 नवंबर को लालकिले के बाहर हुए विस्फोट में 15 लोग मारे गए थे। एजेंसी ने नौ दिसंबर को बताया कि मल्ला पर आतंकवादी हमले से संबंधित सबूतों को नष्ट करने का भी आरोप है। एनआईए ने इस मामले में अब तक नौ लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें तीन डॉक्टर – मुजम्मिल गनई, अदील राथर और शाहीन सईद और एक धार्मिक उपदेशक मौलवी इरफान अहमद वागे शामिल है। अन्य पांच में मल्ला, अमीर राशिद अली, सोयब, जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश और यासिर अहमद डार शामिल हैं।

संपादकीय

2026 में हमें बहुत सारी चीजें अलग तरह से करनी होंगी

बीते वर्ष को देखने के दो तरीके होते हैं। पहला, उसके प्रमुख घटनाक्रमों को यंत्रवत रूप से रेखांकित भर करनाय और दूसरा, उनका मूल्यांकन करना, उनके प्रासंगिक पहलुओं को चिह्नित करना और यह देखना कि आने वाले वर्ष में क्या किए जाने की आवश्यकता है। मेरे विचार से, 2025 को चार केंद्रीय मुद्दों के लिए याद किया जाएगा रू चुनाव प्रक्रिया की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को लेकर उठते सवालय दिल्ली तथा उससे सटे क्षेत्रों में साफ हवा का संकटय हमारे पड़ोस में जारी उथल–पुथल और ट्रम्प की अप्रत्याशित हरकतों के कारण भारत–अमेरिका संबंधों में पैदा हुई अस्थिरता। बिहार में एसआईआर को जिस तरह से अंजाम दिया गया, और अब जिस तरीके से इसे पूरे देश में किया जा रहा है, वह बहुत सारे प्रश्न अनुत्तरित छोड़ देता है। यहां मतदाता सूची की शुचिता सुनिश्चित करने के चुनाव आयोग के अधिकार पर सवाल नहीं हैं। लेकिन जिस अंदाज में वो अपनी इस जिम्मेदारी का निर्वहन करता है, वह जरूर चिंताओं के दायरे में है। यह धारणा लगातार मजबूत हो रही है कि इस प्रक्रिया में पर्याप्त पारदर्शिता का अभाव है। और यह इस अन्य धारणा का परिणाम है कि संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार चुनाव आयोग की स्वायत्तता अपेक्षित स्तर की नहीं रह गई है। वास्तविक लोकतंत्र यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रतिस्पर्धी दलों के बीच होने वाले चुनाव निष्पक्ष हों और उनके नियम सभी पर समान रूप से लागू हों। इसके लिए स्वतंत्र चुनाव आयोग अनिवार्य है। और इसके लिए यह जरूरी है कि उसके आयुक्त तटस्थ हों। वे किसी दल के प्रति झुके न हों। यदि यह विश्वास खंडित होता है तो चुनावों की वैधता सवालों के घेरे में आ जाती है। 2025 ने इस संदर्भ में एक चेतावनी दी है। 2026 को आवश्यक सुधार सुनिश्चित करने होंगे। 2025 में जारी वायु संकट– जिसने उत्तर भारत को हांफने पर मजबूर कर दिया और दिल्ली के निवासियों का दम घोंट दिया– ने भी नागरिकों को यह पूछने पर विवश किया कि यह समस्या हर साल क्यों दोहराई जाती है? इससे भी अधिक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जब इसके भयावह नतीजे अच्छी तरह से मालूम हैं, तब भी सरकार इसे ठीक करने के लिए ठोस कदम क्यों नहीं उठाती? सरकार को इस आपदा के सामने असहाय देखना इस धारणा को जन्म देता है कि सत्ता में बैठे लोग केवल वहीं पर सक्रिय होते हैं, जहां वोट दांव पर हों। नागरिकों की ओर से यदि कोई संगठित पहल नहीं हो तो सरकारें बस इंतजार करती रहती हैं कि सालाना संकट अपने आप टल जाए। लेकिन 2025 ने संकेत दिया है कि लोग अब कह रहे हैं रू बहुत हुआ। 2026 वह वर्ष हो सकता है, जब नागरिक जवाबदेही की मांग करें। और तब सरकार को कार्रवाई करनी ही होगी। अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर, पहले नेपाल और फिर बांग्लादेश में उभरे जेन–जी विद्रोह ने भारत को अलग–थलग करने की चीन और पाकिस्तान की दुर्भावनापूर्ण मंशाओं को आगे बढ़ाने में मदद ही की। विशेष रूप से बांग्लादेश में शेख हसीना को उनके शासन के प्रति बढ़ती अलोकप्रियता के बारे में समय रहते सचेत न कर पाना हमारी कूटनीतिक विफलता रही। लगता है कि हमने वहां के विपक्ष के साथ संवाद के रास्ते खुले रखे बिना अपने सारे दांव उन्हीं पर लगा दिए। जमात–ए–इस्लामी जैसे अतिवादी दलों और भारत–विरोधी तत्वों को वित्तपोषित और प्रोत्साहित करने में पाकिस्तान की भूमिका का आकलन न कर पाना भी एक चूक रही। उधर पाकिस्तान में, कट्टरपंथी जनरल मुनीर का उभार चिंता का विषय है। मुनीर का ट्रम्प के साथ भोजन करना, सऊदी अरब को रिझाना और चीन के साथ तालमेल बैठाना भी इसी कड़ी में है। ट्रम्प पर हमारा भरोसा भी गलत साबित हुआ और उनके पक्षपातपूर्ण टैरिफों का हमने आक्रामक ढंग से प्रतिकार भी नहीं किया। जबकि चीन ने ट्रम्प की धमकियों का डटकर सामना किया और अब ट्रम्प अमेरिका और चीन से मिलकर बने 'जी–2' की बात कर रहे हैं। हम आशा ही कर सकते हैं कि 2026 में हालात बेहतर होंगे। नए साल की शुरुआत बीते साल पर आत्ममंथन का अवसर भी देती है। 2026 इसी के लिए एक आमंत्रण है, और आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने का भी। नववर्ष की शुभकामनाएं। हम आशा ही कर सकते हैं कि 2026 में हालात 2025 की तुलना में बेहतर होंगे। नए साल की शुरुआत बीते साल पर आत्ममंथन का अवसर देती है। 2026 इसी के लिए एक आमंत्रण है। आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने का भी।

राशिफल

मेष :– योजनाओं के फलीभूत होने से मन प्रसन्न होगा। मस्त–मौला मन व्यर्थ के कायरे में समय जाया कर महत्वपूर्ण कायरे के प्रति लापरवाह होगा। शिक्षा–प्रतियोगिता की दिशा में किया गया परिश्रम तीव्र होगा।
वृषभ :– नयी घरेलू जिम्मेदारियों के पैदा होने से व्यय संभव। प्रयासरत कोई महत्वपूर्ण कार्य हल होने से मन प्रसन्न होगा। नये कायरें के क्रियान्वयन हेतु प्रयत्न तीव्र होगा। जरूरी कायरे की समय से पूर्ति करें।
मिथुन :– नये क्षेत्रों मे प्रयास से लाभ संभव। समस्याओं के समाधान से उत्साह में वृद्धि होगी। नये संबंधों के सहयोग से आर्थिक कठिनाइयां दूर होंगी। जीवन साथी के स्वास्य के प्रति सतर्कता बरतें।
कर्क :– सुख–साधनों की लालसा बढ़ेगी। महत्वपूर्ण कार्य की पूर्ति में असमर्थता जैसी स्थिति मन में निराशा पैदा करेगी। पुरानी घटनाओं के स्मरण से मन को कष्ट संभव। रोजगार में क्षमता का पूर्ण लाभ मिलेगा।
सिंह :– कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मन दुविधाग्रस्त होगा। मित्रवत संबंधों का लाभ प्राप्त होगा। आवेश में लिये गये निर्णय से पश्चाताप संभव। घर में किसी मेहमान के आगमन से व्यय संभव।
कन्या :– मन को सकारात्मक दिशा की ओर केंद्रित करें। भाग्य से प्राप्त अच्छी बुरी सभी स्थितियों के साथ समझौतावादी बने। अपने सुख–दुख छोड़ परिजनों के सुख के बारे में सोचें। आलस्य कतई न करें।
तुला :– पुरानी गलतियों से सीख लेते हुए वर्तमान को सुधारें। अच्छे कायरें से परिजनों के दिल में जगह बनायें। विद्यार्थी शिक्षा में लापरवाही न बरनें। जीवन साथी के स्वास्य के प्रति सचेत रहें।
वृश्चिक :– भौतिक सुख–साधनों की लालसा बढ़ेगी। महत्वपूर्ण कार्य की पूर्ति में असमर्थता जैसी स्थिति मन को निराश करेगी। किसी नयी दिशा में सकारात्मक सोच अवश्य रंग लायेगी।
धनु :– मूल्यवान समय को व्यर्थ के कायरें में न जाया करें। व्यावसायिक यात्रा द्वारा लाभ संभव। संवेदनशील शरीर ग्रहों की प्रतिकूलता से बीमार पड़ सकते हैं। जरूरी कायरे की पूर्ति समय से करें।
मकर :– सब कुछ सामान्य होते हुए भी मन अरुचि का शिकार होगा। रोजगार में लाभ के नये अवसर मिलेंगे। पिता के स्वास्य के प्रति सचेत रहें। किसी मेहमान के आगमन से घर में खुशहाल वातावरण रहेगा।
कुंभ :– किसी की अस्वस्थता से परिवार में कष्टप्रद माहौल होगा। महत्वपूर्ण कार्यवश घर से दूर जाना पड़ सकता है। महत्वपूर्ण कायरें के प्रति आलस्य न करें। रोजगार में आ रही समस्याओं से निराश न हों।
मीन :– प्रतिभाओं के बावजूद हीन भाव प्रतिभाओं के लाभ से वंचित करेगा। कल्पनाओं में जीना छोड़ भौतिक जगत के अनुकूल चलने का प्रयत्न करें। जीवन साथी के स्वास्य के प्रति सचेत रहें।

कक्षा की दीवारों से बाहर शिक्षा : अनिवार्य उपस्थिति की वैचारिक पड़ताल

– डॉ सत्यवान सौरभ

उच्च शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल छात्रों को डिग्री देना या उन्हें एक निश्चित साँचे में ढालना नहीं है। इसका सार यह भी है कि एक छात्र को उसकी बेड़ियों से मुक्त कर एक चिंतनशील नागरिक बनाना जो स्वतंत्र सोच के योग्य हो। फिर भी भारतीय कॉलेजों और विश्वविद्यालयों ने एक ऐसी प्रणाली लागू की है जहाँ हर छात्र को कक्षा में उपस्थित होना अनिवार्य है, और यह डिग्री शिक्षा की सीमा है, और इससे अधिक पनिगरानी और अनुशासनष नहीं है। यदि किसी की उपस्थिति का भौतिक स्थान सीखने के लिए एक पूर्वापेक्षा बन जाता है, तो ज्ञान यांत्रिक हो जाता है, जिससे जिज्ञासा, संवाद और आलोचनात्मक सोच जैसे अन्य तत्व बाहर हो जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में, सभी छात्र सीखने की खुशी या बौद्धिक जिज्ञासा से नहीं, बल्कि नियमों और दंड से प्रेरित होते हैं। ऐसे वातावरण में, इस मुद्दे के नैतिक और कानूनी आयाम को दिल्ली उच्च न्यायालय के हालिया बयानों द्वारा रेखांकित किया गया है। न्यायालय ने दोहराया कि छात्रों को परीक्षा देने या अकादमिक रूप से आगे बढ़ने का अवसर न देना, यदि उन्होंने ष्कठोर उपस्थिति मानदंडष के अनुसार अपने प्रदर्शन का कम से कम एक अंश दिखाया है, तो यह शिक्षा के होने के कारण का अपमान है। ये बयान इस दृष्टिकोण को व्यक्त करते हैं कि, आज तक, उच्च शिक्षा में छात्र केवल बच्चे नहीं हैं; वे अधिक परिपक्व लोग हैं, जिन्हें अनुभव के साथ आने वाले आत्म–अनुशासन और जिम्मेदारी की आवश्यकता होती है। शिक्षा का मूल्य वास्तव में सीखने की क्षमता के अनुसार मूल्यांकन किया जाना चाहिए, न कि केवल कुछ पाठों में बैठने के अनुसार, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला। यह भारतीय विश्वविद्यालय संस्थानों में पारंपरिक प्रथा को चुनौती देता है जो उपस्थिति को शैक्षिक योग्यता का मुख्य प्रतिबिंब मानता है। इन परिसरों के भीतर पाउलो फ्रेरे की श्आलोचनात्मक शिक्षाशास्त्रश और विशेष रूप से उनका श्बैंकिंग मॉडलश प्रचलित शैक्षिक मॉडल की एक शक्तिशाली आलोचना प्रस्तुत करता है। शिक्षण के उस चरित्र के द्वारा जिसमें शिक्षक ज्ञान के जमाकर्ता होते हैं और छात्र निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, एक शैक्षिक प्रक्रिया फ्रेरे के अनुसार असंतुलित रहती है। इस बैंकिंग मॉडल में, शिक्षक बैंक का दिल होता है, और छात्र मूल रूप से, आज्ञाकारी उपभोक्ता होता है। अनिवार्य उपस्थिति की धारणा केवल इस मॉडल को मजबूत करती है, क्योंकि अब यह छात्र की उपस्थिति है न कि सीखने की गुणवत्ता। इस तरह, शिक्षा संवाद और सहयोग का कार्य बनना बंद कर देती है और नियंत्रण और निगरानी का तंत्र बन जाती है। ऐसे सिस्टम के नैतिक परिणाम गंभीर होते हैं। जैसे ही स्कूल छात्रों को नियमों का पालन करने वालों की श्रृंखला के रूप में देखना शुरू करते हैं, वे उनकी स्वायत्तता और गरिमा छीन लेते हैं। शिक्षा, जो स्वतंत्र सोच और आत्मनिर्णय को उत्पन्न करने का साधन है, अनुशासन उपकरण बन जाती है। और वहाँ, उन्हें यह प्रतिक्रिया मिलती है कि उनकी उपस्थिति महत्वपूर्ण है, यदि नहीं तो समझने, या प्रश्न पूछने के लिए एकमात्र है। समय के साथ, यह मानसिकता स्थापित हो जाती है; कि सीखना बाहरी उत्तेजनाओं के सामने किया जाता है, आंतरिक प्रेरणा के पक्ष में नहीं। नैतिक रूप से, यह आज्ञाकारिता के लिए शिक्षा है, स्वतंत्रता के लिए नहीं। अनिवार्य उपस्थिति के इस कठोर दृष्टिकोण से छात्र स्तर पर कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उच्च शिक्षा कई मायनों में आज तक की तुलना में अधिक जटिल और बहुआयामी है। नए प्रकार के सीखने और अवसर मौजूद हैं जिनमें ऑनलाइन संसाधन, वेब–आधारित सामग्री, अनुसंधान जांच, परियोजनाएं और फील्डवर्क शामिल हैं। इसके साथ कहा गया है, उपस्थिति केवल कक्षा में बैठने जितनी महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है कि ये सफल, वैकल्पिक सीखने के तरीके नजरअंदाज किए जाते हैं। यह शिक्षा को मानक और विशिष्ट बनाता है, क्योंकि ज्ञान का क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है और गतिशील है। अनिवार्य उपस्थिति नीति सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को और बढ़ा देती है। ऐसे छात्र हैं जो आर्थिक कारणों से अंशकालिक काम कर रहे हैं, माता–पिता जो अपने सभी बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, कुछ जो स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, और कई जिन्हें अभी नौकरी नहीं मिली है। ऐसी कठोर उपस्थिति नियम इन विविध परिस्थितियों को नजरअंदाज करते हैं और सभी छात्रों के लिए एक ही उपस्थिति मानक लागू करते हैं। इस संदर्भ में दिल्ली उच्च न्यायालय की चिंता महत्वपूर्ण है, इस अर्थ में कि यह अन्याय और देखभाल के हमले के तहत शिक्षा का मामला है, यह जोर महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निहित करता है कि शिक्षा को न्याय और मानव संवेदनशीलता के संदर्भ से जांचा जाना चाहिए। जब यह छात्रों की वास्तविक स्थिति से अवगत नहीं होता है, जहां वे अपने जीवन में हैं, हम समान अवसर नहीं हैं, समान अवसर की बहुत अवधारणा पतली हो जाती है। फ्रेरे की आलोचनात्मक शिक्षाशास्त्र में, शिक्षा का उपयोग सामाजिक परिवर्तन के एक साधन के रूप में किया जाता है। उनके अनुसार, शिक्षा की भूमिका केवल जानकारी प्रदान करना नहीं है बल्कि चेतना को प्रोत्साहित करना भी है, छात्रों को एक नींव प्रदान करना जो उन्हें अपने सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक वातावरण के साथ आलोचनात्मक रूप से जुड़ने और प्रभाव डालने के लिए सशक्त बनाता है। बैंकिंग मॉडल के अपवाद के साथ, बैंकिंग मॉडल छात्रों को यथास्थिति बनने के लिए सिखाता है। जब शिक्षा को अनिवार्य उपस्थिति के माध्यम से नियंत्रण और अनुशासन के साथ जोड़ा जाता है, तो यह आलोचनात्मक चेतना के गठन में बाधा बन जाती है। यथास्थिति को चुनौती देने और विभिन्न दृष्टिकोणों को देखने के बजाय, छात्र सीखते हैं कि सुरक्षा नियमों के अनुसार अनुरूपता में निहित है। भारतीय उच्च शिक्षा में ऐतिहासिक और संरचनात्मक स्तरों पर, हमें समस्या मिलती है। औपनिवेशिक स्कूलिंग सिस्टम ने प्रशासनिक नियंत्रण और अनुशासन को शिक्षा के मौलिक स्तंभ बना दिया था। स्वतंत्रता के बाद भी कई स्कूल अनजाने में इस ही प्रतिमान में उलझ गए। अनिवार्य उपस्थिति उसी परंपरा का हिस्सा है जो नियंत्रण बनाए रखने की है; शिक्षा को एक नौकरशाही प्रक्रिया की तरह चलाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, उच्च शिक्षा अधिक लचीले, छात्र–केंद्रित और संवाद–आधारित दृष्टिकोणों की ओर बढ़ रही है। दूसरा, उपस्थिति और सीखने का सीधा और प्राकृतिक संबंध नहीं है। कुछ छात्रों के लिए, शिक्षक या शिक्षक–प्रारंभिक गतिविधि उन्हें एक उद्देश्य की भावना प्रदान करती है जब वे केवल एक बैठक में भाग लेने में सक्षम होते हैं लेकिन एक निष्क्रिय तरीके से भाग लेते हैं, जबकि ये सभी छात्र अपने स्वयं के अध्ययन, चर्चा और अनुसंधान के साथ अधिक सीखते हैं। जब विश्वविद्यालय उपस्थिति को सीखने के साथ बराबर करते हैं – वे इस जटिलता को नजरअंदाज करते हैं। ऐसा करने में, शैक्षिक गुणवत्ता को केवल उपस्थिति पर आंका जा सकता है। इसलिए, जो हम जानते हैं उसका वास्तविकता में बहुत कम आधार है। उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय की टिप्पणियों को उच्च शिक्षा की नीतियों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए एक वाहन के रूप में देखा जा सकता है। उनके लेंस के माध्यम से, अदालतें तर्क देती हैं, शिक्षा सीखने के बारे में होनी चाहिए, न कि दंड के बारे में। उपस्थिति को पूरी तरह से समाप्त करना अव्यावहारिक हो सकता है, लेकिन यहाँ बहुत कुछ दांव पर है, जिसमें इसे अनिवार्य और गंभीर बनाना शामिल है। हमें उपस्थिति को सीखने के लिए एक अतिरिक्त सहायता के रूप में देखना चाहिए न कि स्वयं अंत लक्ष्य के रूप में। यदि हमारी शिक्षा संवाद, भागीदारी और साझेदारी के माध्यम से समृद्ध होती है, तो फ्रेरे का शिक्षाशास्त्रीय दृष्टिकोण हमें दिखाता है कि कैसे। जब शिक्षक और छात्र सीखने की प्रक्रिया में साझेदार के रूप में काम करते हैं, तो सीखना जीवंत और मूल्यवान हो जाता है। शिक्षा को मानवीय और लोकतांत्रिक बनना चाहिए, यदि विश्वविद्यालयों में संस्थान सीखने की गुणवत्ता, भागीदारी और आलोचनात्मक संवाद को महत्व देते हैं और अनिवार्य नामांकन की गारंटी नहीं देते हैं। इस प्रकार छात्र न केवल पाठ्यक्रम को पूरा करेंगे, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी के बारे में भी ज्ञान प्राप्त करेंगे। अंत में, प्रश्न उपस्थिति का नहीं है, बल्कि हमारी समझ का है कि शिक्षा क्या है। यदि शिक्षा को केवल अनुशासन और नियंत्रण की प्रणाली के रूप में देखा जाता है, तो यह बैंकिंग मॉडल के संदर्भ में सीमित रहेगी। लेकिन अगर शिक्षा चेतना, स्वतंत्रता और बौद्धिक विकास का वाहन है, तो अनिवार्य उपस्थिति जैसी नीतियों पर सवाल उठाना एक आवश्यकता होनी चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तावित सुझाव और पाउलो फ्रेरे के विचार इस तरह सोचने के लिए मार्गदर्शन के रूप में काम करते हैंरू भारतीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा का उद्देश्य समर्पण नहीं है; यह प्रबोधन, संवाद और मानवता का विकास है।

सावित्रीबाई फुले : शिक्षा, समानता और सामाजिक क्रांति की अग्रदूत

–सुनील कुमार महला

सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका, 19 वीं सदी की प्रमुख समाज सुधारक और कवयित्री थीं। कहना ग़लत नहीं होगा कि उन्होंने महिला शिक्षा और सशक्तीकरण की दिशा में तथा जाति एवं लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करने में पथप्रदर्शक का कार्य किया और वे अपने आप में नारी सशक्तीकरण की एक मिसाल मानी जाती हैं। उनका जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव (जिला सतारा) में हुआ था। पाठकों को बताता चलूं कि उनकी माताजी का नाम श्रीमती लक्ष्मीबाई तथा पिता का नाम श्री खन्दोजी नेवसे पाटिल था तथा उनका विवाह 1841 में महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फुले(ज्योतिबा फुले) से हुआ था और उन्होंने उनके साथ मिलकर स्त्री शिक्षा और सामाजिक समानता की नींव रखी। यहां पाठकों को यह भी बताता चलूं कि ज्योतिबा फुले थॉमस पाइन की पुस्तक 'द राइट्स ऑफ मैन' से प्रभावित थे और उनका यह मानना घ्था कि सामाजिक बुराइयों का मुकाबला करने का एकमात्र तरीका महिलाओं व निम्न वर्ग के लोगों को शिक्षा प्रदान करना था। वर्ष 1840 में जब बाल विवाह एक सामान्य बात थी, उस समय मात्र 10 साल की उम्र में ही सावित्रीबाई फुले का विवाह ज्योतिराव फुले, जिन्हें ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है, से कर दिया गया था, जो कि स्वयं उस समय मात्र 13 वर्ष के थे। बाद के समय में इस विवाहित जोड़े ने बाल विवाह(कम उम्र में विवाह) का विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह की भी वकालत की।पाठकों को बताता चलूं कि महात्मा ज्योतिराव को महिलाओं और पिछड़े वर्गों को शिक्षित करने के उनके प्रयासों और कार्यों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। विकीपीडिया पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार श्ज्योतिराव, जो बाद में ज्योतिबा के नाम से भी जाने गए सावित्रीबाई फुले के संरक्षक, गुरु और समर्थक थे। यहां पाठकों को यह भी बताता चलूं कि 11 मई, 1888 को महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्त्ता विट्ठलराव कृष्णजी वांडेकर द्वारा उन्हें(ज्योतिबा फुले को) 'महात्मा' की उपाधि से सम्मानित किया गया था। यहां उल्लेखनीय है कि वर्ष 1852 तक फुले ने तीन स्कूलों की स्थापना की थी, लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद धन की कमी के कारण वर्ष 1858 तक ये स्कूल बंद हो गए थे।ज्योतिराव ने ब्राह्मणों और अन्य उच्च जातियों की रूढ़िवादी मान्यताओं का घोर विरोध किया और उन्हें श्पाखंडीश करार दिया।कई लोगों का यह भी मानना है कि यह ज्योतिबा फुले ही थे, जिन्होंने सबसे पहले श्दलितश शब्द का इस्तेमाल उन उत्पीड़ित जनता के चित्रण के लिये किया था, जिन्हें अक्सर श्वर्ण व्यवस्थाश से बाहर रखा जाता था। बहरहाल, ऊपर इस आलेख में चर्चा कर चुका हूं कि सावित्रीबाई फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका और महान समाज सुधारक थीं, जिन्होंने उस समय शिक्षा का अलख जगाया जब लड़कियों को पढ़ाना पाप माना जाता था। उन्होंने अपने जीवन में अपमान, विरोध और कठिनाइयों का सामना करते हुए भी महिला शिक्षा और दलित–वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए निरंतर संघर्ष किया। ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर उन्होंने बालिकाओं और शोषित वर्गों के लिए विद्यालय स्थापित किए और समाज में समानता की भावना को मजबूत किया। वे केवल शिक्षिका ही नहीं, बल्कि कवयित्री और प्रखर विचारक भी थीं, जिनकी रचनाएँ सामाजिक चेतना को जाग्रत करती हैं। सावित्रीबाई फुले का संपूर्ण जीवन साहस, करुणा और सामाजिक परिवर्तन की अमर प्रेरणा है। वास्तव में उन्होंने अपने जीवन को एक मिशन की तरह से जीया, जिसका उद्देश्य था विधवा विवाह करवाना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और महिलाओ को शिक्षित बनाना।श उन्हें मराठी की आदिकवियत्री के रूप में भी जाना जाता था। दूसरे शब्दों में कहें तो सावित्रीबाई एक सशक्त कवयित्री भी थीं। उनकी प्रमुख कृतियाँ 'काव्यफुले' और 'बावन काशी सुबोध रत्नाकर' हैं, जिनमें सामाजिक चेतना, शिक्षा और समानता का संदेश मिलता है। यहां यह भी गौरतलब है कि 5 सितंबर 1848 में पुणे में अपने पति के साथ मिलकर विभिन्न जातियों की नौ छात्राओं के साथ उन्होंने महिलाओं के लिए उस समय एक विद्यालय की स्थापना की, जिस समय लड़कियों की शिक्षा पर पाबंदी थी। उस समय एक वर्ष में सावित्रीबाई और महात्मा फुले पाँच नये विद्यालय खोलने में सफल हुए।श्रीमती फुले पहले किसान स्कूल की संस्थापक थीं तथा यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने बहुत पहले 1848 में पुणे में देश का पहला बालिका विद्यालय शुरू करके लड़कियों के लिए एक प्रकार से शिक्षा की नींव रखी। वास्तव में यह वह समय था जब लड़कियों और दलितों की शिक्षा का समाज में कड़ा विरोध होता था। कहते हैं कि जब वे पढ़ाने जाती थीं तो लोगों द्वारा उनका अपमान किया जाता था, गालियाँ और उन पर पत्थर तक फेंके जाते थे, फिर भी उन्होंने शिक्षा का मार्ग नहीं छोड़ा। यह भी जानकारी मिलती है कि वे रास्ते में एक अतिरिक्त साड़ी लेकर चलती थीं, ताकि उन पर गंदगी फेंके जाने पर वे उसे बदल सकें और स्कूल जा सकें। वास्तव में यह उनके अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प का प्रतीक कहा जा सकता है। जैसा कि इस आलेख में ऊपर भी चर्चा कर चुका हूं कि अपने समय में उन्होंने छुआछूत, जाति–भेद, बाल विवाह और सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई। विधवाओं के पुनर्विवाह और गर्भवती विधवाओं के संरक्षण के लिए उन्होंने आश्रय गृह (बालहत्या प्रतिबंधक गृह) की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे शोषितों, महिलाओं और दलितों के अधिकारों की सशक्त पक्षधर थीं।वर्ष 1852 में सावित्रीबाई ने महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये 'महिला सेवा मंडल' की शुरुआत की।सावित्रीबाई ने एक महिला सभा का आह्वान किया, जहाँ सभी जातियों के सदस्यों का स्वागत किया गया और सभी से एक साथ मंच पर बैठने की अपेक्षा की गई।उन्होंने वर्ष 1854 में 'काव्या फुले' और वर्ष 1892 में 'बावन काशी सुबोध रत्नाकर' का प्रकाशन किया। उनका काव्य–संग्रह 'काव्या फुले' सामाजिक चेतना से ओत–प्रोत रचनाओं का महत्वपूर्ण संकलन है। इस कृति में उन्होंने स्त्रियों की दुर्दशा, शिक्षा के महत्व, जातिगत भेदभाव, अंधविश्वास और सामाजिक अन्याय जैसे विषयों को सरल किंतु प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत किया है। 'काव्या फुले' की कविताएँ लोगों को सोचने, प्रश्न करने और समानता की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। इनमें करुणा, विद्रोह और सुधार की स्पष्ट भावना दिखाई देती है, जिससे यह कृति उस समय के शोषित–वंचित समाज की सशक्त आवाज़ बन गई। इसके अलावा वर्ष 1892 में प्रकाशित 'बावन काशी सुबोध रत्नाकर' सावित्रीबाई फुले की एक और महत्वपूर्ण साहित्यिक रचना मानी जाती है। इस कृति में बावन सुभाषितों या शिक्षाप्रद पद्यों के माध्यम से उन्होंने नैतिकता, सदाचार, शिक्षा, मानवीय मूल्यों और सामाजिक सुधार के विचारों को प्रस्तुत किया। यह ग्रंथ सरल और सुबोध भाषा में लिखा गया है ताकि सामान्य जन, विशेषकर महिलाएँ और वंचित वर्ग, इसे आसानी से समझ सकें। 'बावन काशी सुबोध रत्नाकर' का उद्देश्य लोगों को आत्मचिंतन, विवेक और सही आचरण की ओर प्रेरित करना था। इस रचना के माध्यम से सावित्रीबाई फुले ने यह स्पष्ट किया कि शिक्षा केवल अक्षर–ज्ञान नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और मानवीय गरिमा की स्थापना का माध्यम है। अपनी कविता 'गो, गेट एजुकेशन' में वह उत्पीड़ित समुदायों से शिक्षा प्राप्त करने और उत्पीड़न की जंजीरों से मुक्त होने का आग्रह करती हैं। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करते हुए बाल विवाह के खिलाफ एक साथ अभियान चलाया। वर्ष 1873 में महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले ने समाज में व्याप्त ब्राह्मणवादी वर्चस्व, जातिगत भेदभाव और दहेज प्रथा के विरुद्ध एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पहला 'सत्यशोधक विवाह' प्रारंभ कराया।

दूसरे शब्दों में कहें तो सत्यशोधक समाज (द ट्रुथ–सीकर्स सोसाइटी) की स्थापना 24 सितंबर, 1873 को ज्योतिराव–सावित्रीबाई और अन्य समान विचारधारा वाले लोगों द्वारा की गई थी।इस विवाह की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें न तो दहेज लिया जाता था, और न ही किसी ब्राह्मण पुजारी की आवश्यकता पड़ती थी और न ही वेददृमंत्रों अथवा जटिल कर्मकांडों का पालन किया जाता था। सच तो यह है कि विवाह को एक सामाजिक समझौते के रूप में देखा गया, न कि धार्मिक कर्मकांड के रूप में।इस सत्यशोधक विवाह का उद्देश्य था–स्त्रीदृपुरुष समानता, सरलता और सामाजिक न्याय। इसमें दोनों पक्षों द्वारा समान शपथ ली जाती थी कि वे एक–दूसरे का सम्मान करेंगे, स्त्री को दासी नहीं बल्कि समान अधिकारों वाली साथी मानेंगे और जाति–आधारित भेदभाव का पालन नहीं करेंगे। यह विवाह व्यवस्था उस समय के समाज के लिए क्रांतिकारी विचार थी, क्योंकि इससे न केवल दहेज जैसी कुप्रथाओं पर चोट हुई, बल्कि ब्राह्मणवादी धार्मिक एकाधिकार को भी खुली चुनौती मिली।इस पहल ने विवाह संस्था को मानवीय, नैतिक और समानतावादी मूल्यों से जोड़ने का कार्य किया और आगे चलकर समाज सुधार आंदोलनों के लिए एक मजबूत वैचारिक आधार बना। सत्यशोधक विवाह आज भी सामाजिक सुधार और समानता की दिशा में फुले दंपति की दूरदर्शिता का सशक्त उदाहरण माना जाता है। इतना ही नहीं,वर्ष 1848 में फुले ने पूना में लड़कियों, शूद्रों एवं अति–शूद्रों के लिये एक स्कूल शुरू किया तथा 1850 के दशक में फुले दंपत्ति ने दो शैक्षिक ट्रस्टों की शुरुआत की– नेटिव फीमेल स्कूल (पुणे) और 'द सोसाइटी फॉर प्रोमोटिंग द एजुकेशन ऑफ महार'– जिसके तहत कई स्कूल शामिल थे। वर्ष 1853 में उन्होंने गर्भवती विधवाओं के लिये सुरक्षित प्रसव हेतु और सामाजिक मानदंडों के कारण शिशुहत्या की प्रथा को समाप्त करने के लिये एक देखभाल केंद्र खोला। दूसरे शब्दों में कहें तो विधवाओं और बलात्कार पीड़ित महिलाओं के लिए उन्होंने पहला बालहत्या–निरोधक गृह खोला।गौरतलब है कि बालहत्या प्रतिबंधक गृह (शिशु हत्या निवारण गृह) उनके ही घर में शुरू हुआ। यह एक कटु सत्य है कि फुले ने समाज में सामाजिक परिवर्तनों की वकालत की तथा प्रचलित परंपराओं के खिलाफ कदम उठाया, जिनमें आर्थिक विवाह, अंतर–जातीय विवाह, बाल विवाह का उन्मूलन और विधवा पुनर्विवाह शामिल हैं। साथ ही सत्य शोधक समाज की स्थापना निम्न जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को शिक्षा देने तथा समाज की शोषक परंपरा से अवगत कराने के उद्देश्य से की गई थी। पाठकों को बताता चलूं कि सावित्रीबाई फुले केवल भारत की पहली महिला शिक्षिका ही नहीं थीं, बल्कि वे प्रशिक्षित अध्यापिका भी थीं। उन्होंने पुणे और अहमदनगर में शिक्षक प्रशिक्षण लिया था, जो उस दौर में महिलाओं के लिए लगभग असंभव माना जाता था।वे पाठ्य–पुस्तकों की लेखिका भी थीं तथा उन्होंने बच्चों के लिए स्वयं पाठ्य सामग्री और कविताएँ लिखीं, ताकि शिक्षा सरल और व्यवहारिक बन सके। उनकी काव्य–कृतियाँ शिक्षा को सामाजिक बदलाव से जोड़ती थीं। इतना ही नहीं, फुले दंपत्ति ने अपने घर में दलित और वंचित वर्ग के बच्चों को आश्रय और शिक्षा दी, जिससे समाज में समानता का संदेश गया। जब दलितों को सार्वजनिक कुओं से पानी लेने नहीं दिया जाता था, तब सावित्रीबाई ने अपने घर का कुआँ सभी के लिए खोल दिया।वे सत्यशोधक समाज की अग्रणी नेता थीं। वे केवल सदस्य मात्र नहीं थीं, बल्कि सत्यशोधक समाज की सक्रिय वैचारिक मार्गदर्शक थीं और महिलाओं को संगठन से जोड़ने में उनकी अहम भूमिका थी। जानकारी मिलती है कि प्लेग पीड़ितों की सेवा करते हुए उनका निधन हो गया था। 1897 में पुणे में प्लेग फैला, तब सावित्रीबाई स्वयं रोगियों को कंधे पर उठाकर अस्पताल ले जाती थीं। इसी सेवा के दौरान वे संक्रमित हुईं और 10 मार्च 1897 को उनका निधन हुआ,वे सचमुच सेवा में शहीद हुईं। कहना ग़लत नहीं होगा कि उन्होंने आधुनिक नारीवाद की आधारशिला र

उत्तर प्रदेश में सिंचाई क्रांति, तीन बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के लिए नाबार्ड ने स्वीकृत की धनराशि

बुंदेलखंड में अर्जुन नहर, पूर्वांचल के लिए सरयू नहर और पश्चिमी यूपी में मध्यगंगा परियोजना चरण–2 का होगा निर्माण

उत्तर प्रदेश में सिंचाई क्षमता के पूर्ण विकास के लिए नाबार्ड ने जारी किए 6,431.34 करोड रुपये

पूर्वी, पश्चिमी यूपी के साथ बुंदेलखंड में दूर होगी सिंचाई, पेयजल और भूगर्भ जल की समस्या

लखनऊ ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सिंचाई क्षमता का पूर्ण विकास करने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से प्रदेश ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की दीर्घकालिक सिंचाई कोष योजना (एटीआईएफ) के तहत प्रदेश में 3 बड़ी नहर परियोजनाओं के विकास कार्य के लिए नाबार्ड की ओर से 6,431.34 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। इसके तहत बुंदेलखंड क्षेत्र में अर्जुन सहायक नहर, पूर्वांचल के क्षेत्र में सरयू नहर और संभल, मुरादाबाद, अमरोहा जनपद में मध्य गंगा नहर परियोजना के दूसरे चरण का निर्माण किया जाएगा। ये परियोजनाएं पूर्वी, पश्चिमी यूपी में बाढ़ नियंत्रण के साथ बुंदेलखंड के सूखा प्रभावित क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का विकास करने के साथ कृषि उत्पादन और उत्पादन क्षेत्र दोनों में बढ़ोतरी लाएगीं। साथ ही नदियों के चौनलाइजेशन से ग्लोबल वार्मिंग की चुनौति का समाना करने में भी प्रदेश को सक्षम बनाएगीं।

बुंदेलखंड में अर्जुन सहायक परियोजना का होगा विकास कार्य जल्द पूरा

केंद्र सरकार की दीर्घकालिक सिंचाई कोष योजना के तहत नाबार्ड के सहयोग से देश के 18 राज्यों में 99 मध्यम और प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण और क्षमता विस्तार किया जा रहा है। मुख्य सचिव के साथ नाबार्ड के अधिकारियों ने बैठक में बताया कि इस क्रम में बुंदेलखंड के सूखा प्रभावित क्षेत्र में अर्जुन सहायक परियोजना के लिए 1,353.86 करोड़ रुपये स्वीकृत किया गया है। ये परियोजना महोबा, हमीरपुर और बांदा जिलों को कवर करती है। बुंदेलखंड की धसान नदी पर बनी परियोजना के कई हिस्सों का काम पूरा हो चुका है, स्वीकृत धनराशि से विशेष रूप से हमीरपुर जिले में शेष कार्य को जल्द पूरा किया जाएगा। परियोजना के पूरा होने से बुंदेलखंड क्षेत्र के सूखाग्रस्त किसानों की बारिश पर निर्भरता कम होगी ही, उत्पादन और उत्पादन क्षेत्र दोनों में वृद्धि होगी। साथ ही ये परियोजना क्षेत्र में पेयजल संकट और मवेशियों के लिए भी जल उपलब्ध करायेगी, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी।

सरयू नहर परियोजना से लाभान्वित होगें 30 लाख से अधिक किसान

जल शक्ति मंत्रालय की एलटीआईएफ योजना के तहत यूपी की दूसरी महत्वपूर्ण परियोजना सरयू नहर के लिए 1,899.35 करोड रुपये स्वीकृत किये गये हैं। ये परियोजना बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोण्डा, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और गोरखपुर जिलों में फैली हुई है। परियोजना के निर्माण से पूर्वी उत्तर प्रदेश के घनी आबादी वाले इन जिलों को जल संकट से निजात मिलेगी। साथ ही सरयू, राप्ती, बांणगंगा और रोहिनी नदी के अतिरेक पानी का चौनलाईजेशन कर कृषि क्षेत्र और उत्पादन में भी वृद्धि लाएगी। परियोजना पूरा होने से 6,227 गांवों के 30 लाख से अधिक किसानों को लाभ होगा और 15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सुनियोजित सिंचाई की सुविधा मिलेगी। साथ ही सिंचाई, पेयजल और मत्स्य पालन के अवसर भी बढ़ेंगे।

उत्तर प्रदेश में सिंचाई क्रांति, तीन बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के लिए नाबार्ड ने स्वीकृत की धनराशि

नाबार्ड ने जारी किए
6,431.34 करोड रुपये

सरयू नहर परियोजना से लाभान्वित होगें
30 लाख से अधिक किसान

सरयू नहर के लिए
1,899.35 करोड रुपये स्वीकृत

बुंदेलखंड में अर्जुन सहायक परियोजना का होगा विकास कार्य जल्द पूरा
1,353.86 करोड़ रुपये स्वीकृत

पश्चिमी यूपी में मध्यगंगा चरण-2 का निर्माण जल्द होगा पूरा
3,178.04 करोड रुपये स्वीकृत

पश्चिमी यूपी में मध्यगंगा चरण–2 का निर्माण जल्द होगा पूरा

इस क्रम में तीसरी परियोजना मध्य गंगा चरण–2 को स्वीकृति मिली है, जिसके लिए नाबार्ड ने 3,178.04 करोड रुपये स्वीकृत किए है। मध्य गंगा चरण–2 के तहत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संभल, मुरादाबाद और अमरोहा जिले विशेषतौर पर लाभान्वित होगें। परियोजना के निर्माण से गंगा बेसिन के क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई क्षमता में अभूतपूर्व सुधार होगा। नाबार्ड के अधिकारियों ने बैठक में बताया कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से उत्तर प्रदेश के पूर्वी, पश्चिमी और बुंदेलखंड में सिंचाई व्यवस्था के साथ कृषि और संबद्ध क्षेत्र से जुड़े किसानों की आय बढ़ेगी। साथ ही ही ग्लोबल वार्मिंग के संकट का सामना करने में भी प्रदेश को सक्षम बनाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के मुताबिक इन परियोजनाओं के पूरा होने से प्रदेश में न केवल कृषि उत्पादन और उत्पादन क्षेत्र बढ़ेगा, साथ ही पेय जल संकट, मतस्य पालन और संबद्ध कार्यों में भी बढ़ोतरी होगी। प्रदेश के किसानों की आय में बढ़ोतरी के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

बीजेपी विधायक का निधन, योंगी ने परिवार को बंधाया ढांढस, अंतिम यात्रा में उमड़े हजारों लोग

संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में फरीदपुर से भाजपा विधायक रहे प्रोफेसर डॉ. श्याम बिहारी लाल के निधन के बाद शनिवार को शोक का माहौल रहा। उनके निधन के दूसरे दिन सुबह 11 बजकर 43 मिनट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शक्ति नगर कॉलोनी स्थित उनके आवास पहुंचे। मुख्यमंत्री ने दिवंगत विधायक की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और शोकाकुल परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। जानकारी के अनुसार, प्रोफेसर डॉ. श्याम बिहारी लाल शुक्रवार को सर्किट हाउस में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह की बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। बैठक में उनका पुराना अंदाज भी दिखा। उन्होंने सहपाठी मीरगंज विधायक डीसी वर्मा से हंसी–ठिठोली कर ली। फिर अचानक कुछ ऐसा घटा, जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। बैठक समाप्त होने के बाद भोजन के दौरान उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तुरंत उपचार दिया गया, लेकिन करीब एक घंटे बाद उनका निधन हो गया। डॉक्टरों ने मृत्यु का कारण हृदयाघात बताया है। उनके आकस्मिक निधन से राजनीतिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक क्षेत्र में भी गहरा शोक व्याप्त है। शनिवार को उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग उनके आवास पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवंगत विधायक की पत्नी, बेटियों और बेटे से मुलाकात कर शोक संवेदनाएं व्यक्त कीं और परिवार की कुशलक्षेम जानी। इस दौरान वन राज्यमंत्री डॉ. अरुण कुमार सक्सेना भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने पूरे परिवार से मिलकर गहरा दुख व्यक्त किया और करीब 15 मिनट रुकने के बाद वहां से रवाना हो गए। दोपहर करीब 12 बजे शक्ति नगर स्थित आवास से विधायक की अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए।

उनका अंतिम संस्कार फरीदपुर के स्टेशन रोड स्थित श्मशान भूमि पर किया जाएगा। अंतिम यात्रा और अंतिम संस्कार को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। विधायक के कार्यालय से लेकर श्मशान भूमि तक पुलिस और पीएसी बल की व्यापक तैनाती की गई है।

लखनऊ एयरपोर्ट से 4 उड़ानें घंटों लेट

घने कोहरे के कारण दिल्ली, भुवनेश्वर और हैदराबाद जाने वाली फ्लाइटें 2 घंटे देर

संवाददाता

लखनऊ। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर खराब मौसम का असर शनिवार को उड़ानों के संचालन पर साफ दिखा। कोहरे और विजिबिलिटी कम होने के चलते दिल्ली, भुवनेश्वर और हैदराबाद जाने वाली कई उड़ानें अपने निर्धारित समय से देरी से रवाना हुईं। इससे यात्रियों को एयरपोर्ट पर लंबा इंतजार करना पड़ा और कई लोगों की आगे की यात्रा भी प्रभावित हुई। खराब मौसम के चलते दिल्ली और भुवनेश्वर रूट पर उड़ानों में सबसे अधिक देरी दर्ज की गई। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट आईएक्स–1058, जो भुवनेश्वर से दिल्ली के लिए निर्धारित थी, अपने तय समय 13.05 बजे की बजाय करीब 2 घंटे 40 मिनट की देरी से रवाना हुई। इसी तरह एयर इंडिया की फ्लाइट एआई–9757 भी इसी रूट पर खराब मौसम की वजह से काफी देर से उड़ान भर सकी। इन उड़ानों का गंतव्य नई दिल्ली और भुवनेश्वर रहा। वहीं इंडिगो की फ्लाइट 6ई–453, जो हैदराबाद के लिए रवाना होनी थी, वह भी खराब मौसम के कारण अपने निर्धारित समय से 34 मिनट देरी से उड़ान भर सकी। उड़ानों में देरी से एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ बढ़ गई। कई यात्रियों ने बताया कि कोहरे के कारण लगातार अपडेट बदलते रहे, जिससे अनिश्चितता बनी रही। कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ने वाले यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा, वहीं बुजुर्गों और बच्चों के साथ यात्रा कर रहे लोगों को भी दिक्कतें झेलनी पड़ीं।

संक्षिप्त

मदरसा बोर्ड का टाइम टेबल जारी, 8 फरवरी से 14 फरवरी के बीच होंगी परीक्षाएं

संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड ने परीक्षा तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। मदरसा बोर्ड के जारी किए गए टाइम टेबल के अनुसार, 8 फरवरी से 14 फरवरी के बीच परीक्षाएं होंगी। मदरसा शिक्षा परिषद् ने वर्ष 2026 में होने वाले मुंशी (सेकंडरी फारसी), मौलवी (सेकेंडरी अरबी) और आलिम (सीनियर सेकेंडरी अरबीध्फारसी) की परीक्षाओं के लिए यह टाइम टेबल जारी किया है। मदरसा बोर्ड की ओर से जारी किए गए टाइम टेबल के अनुसार परीक्षाएं दो पालियों में आयोजित की जाएंगी। पहली पाली में सुबह 8.00 बजे से 11.00 बजे तक परीक्षा होगी। जबकि दूसरी पाली में दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक परीक्षा चलेगी। शुक्रवार को एक ही पाली में परीक्षा होगी। इस वर्ष लगभग 80 हजार परीक्षार्थियों ने फॉर्म भरा है। परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड निर्धारित समय से मदरसा बोर्ड के पोर्टल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। इसे छात्र–छात्राएं ऑनलाइन हासिल कर सकेंगे। परीक्षा की सफल आयोजन के लिए मदरसा बोर्ड की ओर से संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो इसके लिए सभी तैयारियां समय से पूरी करने की बात कही गई। परीक्षा की सुरक्षा सख्त और पारदर्शी बनाने के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। सभी सेंटर्स की सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी की जाएगी। परीक्षा केंद्रों को स्थापित करने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। मदरसा बोर्ड के आला अधिकारी सभी केंद्रों का लखनऊ से ऑनलाइन निगरानी करेंगे। मदरसा बोर्ड से जुड़े तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों को परीक्षा को बेहद गंभीरता से लेने की बात कही गई है।

भाजपा विधायक शलभ मणि ने की पुलिस भर्ती में आयु-सीमा में छूट की मांग, सीएम योगी को लिखा पत्र

संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में देवरिया सदर से विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी ने उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी पीएसी, जेल वार्डर एवं समकक्ष पदों पर प्रस्तावित भर्तियों में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु–सीमा में छूट दिए जाने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर मानवीय दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया है। डॉ. त्रिपाठी ने सोशल शनिवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मुख्यमंत्री योगी को भेजे गए पत्र को पोस्ट करते हुए यह जानकारी दी है। उन्होंने इस पत्र में उल्लेख किया है कि इन भर्तियों की तैयारी प्रदेश के लाखों युवा लंबे समय से कर रहे थे, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में हुई देरी के कारण बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आयु–सीमा पार कर चुके हैं। ऐसे में योग्य और परिश्रमी युवा केवल उम्र की बाध्यता के कारण चयन प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं। उन्होने कहा कि आयु–सीमा के कारण अभ्यर्थियों का बाहर होना न सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके परिवारों के लिए भी अत्यंत पीड़ादायक है। कई अभ्यर्थी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं, जिनकी आशाएं इन भर्तियों से जुड़ी हुई थीं। उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि मानवीय आधार पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को कम से कम तीन वर्ष की आयु–सीमा में छूट प्रदान की जाए, जिससे प्रदेश के परिश्रमी युवाओं को न्याय मिल सके और उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने नव वर्ष पर युवाओं को पुलिस में भर्ती होने का अवसर दिया है। प्रदेश पुलिस में 32,679 सिपाही और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित कर लिए गए हैं। बुधवार से शुरू हुई ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आगामी 30 जनवरी तक जारी रहेगी। बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति में नागरिक पुलिस, पीएसी,सशस्त्र पुलिस, विशेष सुरक्षा बल, पीएसी की तीन महिला वाहिनी, घुड़सवार पुलिस के सिपाही और जेल वार्डर के पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं।

धनंजय सिंह पर एफआईआर कराने वाले के घर पहुंचे संदिग्ध

लखनऊ में कुछ दिन पहले जौनपुर के ब्लॉक प्रमुख पति से हुआ था तनाव

संवाददाता

लखनऊ। लखनऊ में पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर एफआईआर दर्ज कराने वाले कौशल किशोर तिवारी के घर बीती रात 7 संदिग्ध लोग पहुंचे। इस पर कौशल ने डायल–112 पर फोन कर और सुशांत गोल्फ सिटी थाने में लिखित शिकायत दी। उनका कहना है कि वे लोग भारी–भारी बैग लेकर आए थे। उन बैग में जान से मारने की चीजें हो सकती हैं। पिछले दिनों हुए विवाद के बाद विपक्षी (ब्लॉक प्रमुख का पति, पूर्व सांसद) लोग मेरी हत्या करा सकते हैं। लोगों के घर के पास आने की सीसीटीवी फुटेज भी है। बता दें कि जौनपुर के महाराजगंज की ब्लॉक प्रमुख मांडवी सिंह के पति विनय सिंह के साथ स्वास्तिका सिटी के लोगों का तनाव हो गया था। स्वस्तिका सिटी निवासी कौशल किशोर तिवारी के अनुसार, 2 जनवरी की रात करीब 10 बजकर 22 मिनट पर एक महिला और छह पुरुष उनके घर के मुख्य गेट पर पहुंचे। सीसीटीवी फुटेज में सभी साफ दिखाई दे रहे हैं। अचानक गेट पर लोगों की मौजूदगी देख कौशल तिवारी ने भीतर से आवाज लगाई तो बाहर खड़े लोग गाली–गलौज करते हुए मौके से भाग निकले। घटना के बाद जब सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई तो संदिग्धों के चेहरे कैमरे में स्पष्ट नजर आए। इससे आशंका जताई जा रही है कि यह सिर्फ डराने की कोशिश नहीं, बल्कि किसी बड़ी साजिश का हिस्सा भी हो सकता है। फुटेज सामने आने के बाद इलाके के लोगों में भी भय का माहौल बन गया है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान की जा रही है। मामले की जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, स्वस्तिका सिटी में एक बार फिर बढ़ते तनाव को देखते हुए पुलिस सतर्कता बढ़ाने की तैयारी में है।

रोजगार और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर आप की पदयात्रा

संजय सिंह बोले, मिर्जापुर से वाराणसी तक यात्रा निकालेंगे

संवाददाता

लखनऊ। आम आदमी पार्टी (आप) उत्तर प्रदेश में अपने आंदोलन को और तेज करने जा रही है। पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने ऐलान किया कि आम आदमी पार्टी 16 जनवरी से अपनी तीसरे चरण की पदयात्रा की शुरुआत करेगी, जो 22 जनवरी तक चलेगी। यह पदयात्रा "रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो" के नारे के साथ मिर्जापुर से शुरू होकर वाराणसी तक जाएगी। इस दौरान करीब 90 से 100 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। संजय सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, जिससे नौजवानों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। प्रयागराज में छात्रों का प्रदर्शन इस बात का सबूत है कि युवा वर्ग सरकार की नीतियों से नाराज है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी कोर्ट से बेरोजगार युवाओं के हक में कोई फैसला आता है, सरकार उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने पहुंच जाती है। आप सांसद ने कहा कि पशुधन विभाग की भर्ती में आरक्षण से छेड़छाड़ की गई है। उनकी पार्टी की सामाजिक न्याय यात्रा का मकसद ओबीसी और दलित समाज को मिले संवैधानिक आरक्षण की रक्षा करना है। उन्होंने दो टूक कहा कि आरक्षण किसी पार्टी की देन नहीं, बल्कि संविधान का अधिकार है। संजय सिंह ने कहा कि यूपी सरकार के दावे और जमीनी हकीकत में बड़ा फर्क है। उन्होंने पुलिस भर्ती में उम्र सीमा सभी के लिए बढ़ाने की मांग की और पुलिस व्यवस्था पर तंज कसते हुए कहा कि "ठांय–ठांय वाली पुलिस पीठ पर मोबाइल रखकर नागरिकों की पहचान बता दे रही है।" उन्होंने कहा कि यूपी राज्य निर्वाचन आयोग और केंद्रीय निर्वाचन आयोग के एसआईआर आंकड़े अलग–अलग हैं। एसआईआर के नाम पर करोड़ों वोटरों के नाम गायब हो रहे हैं। जो यूपी के मतदाता दूसरे प्रदेशों में रह रहे हैं, उनके वोट बने या नहीं, इसकी जांच तक नहीं हुई। संजय सिंह का आरोप है कि चुनाव आयोग को एसआईआर कराने का अधिकार ही नहीं है। आप नेता ने कहा कि ब्राह्मण विधायकों को बैठक में डांटना–फटकारना ठीक नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि झारखंड की बिजली बांग्लादेश को दी जा रही है, जहां हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों पर बीसीसीआई रोक क्यों नहीं लगा रही, जबकि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने पर कोई विरोध नहीं होता।

राजधानी में शीतलहर के साथ ओस की बारिश, गलन से पिघल रहे हाथ

संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में आज कोहरा काफी कम रहा। सुबह ओस की बूंदें महसूस की गईं। तापमान में 5.5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। गलन बढ़ गई है। इसी के चलते सरकार ने 12वीं तक स्कूलों, इंटर कॉलेजों में अगले 3 दिन (3, 4, 5 जनवरी) की छुट्टी घोषित कर दी है। शुक्रवार शाम के बाद चली हवाओं की वजह से आज शनिवार को सुबह कोहरा बीते दिनों के मुकाबले नहीं रहा। कल सुबह विजिबिलिटी 100 मीटर रही, वहीं आज सुबह 1 किमी से ज्यादा दूर तक साफ दिखाई दिखाई। यह मौसम गेहूं, सरसों के लिए अच्छा है। आज न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस (0.8) दर्ज किया गया। वहीं, अधिकतम तापमान 14. 6 डिग्री सेल्सियस (–5.5) तक गिरा। आर्द्रता औसतन 92 दर्ज की गई। वैज्ञानिकों के अनुसार, आज अधिकतम तापमान 18, न्यूनतम 9 डिग्री दर्ज किया जाएगा। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने और आवश्यक न होने पर सुबह–शाम यात्रा से बचने की सलाह दी है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार, 1 जनवरी से निचले क्षोभ मंडल की स्थिरता भंग हुई थी। पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर–पूर्व की ओर बढ़ने के बाद सतह पर तेज हवाएं चलने लगीं, जिससे गतिशील अस्थिरता पैदा हुई। इसका असर यह हुआ कि जमीन के पास जमी कोहरे की परत हट गई।

लोडर चालक ने फंदा लगाकर सुसाइड किया

संवाददाता

लखनऊ। बंथरा थाना क्षेत्र में एक अधेड़ लोडर चालक ने बीती रात फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को नीचे उतारा और पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान बंथरा के खसरवारा गांव निवासी बाल गोविंद रावत (50) के रूप में हुई है। वह टेंपो डाला चलाकर अपने परिवार का भरण–पोषण करते थे। बाल गोविंद के गांव में दो मकान हैं। एक मकान में उनकी पत्नी फूलमती और दो विवाहित बेटे लवकुश और राहुल रहते हैं, जबकि करीब 150 मीटर दूर दूसरे मकान में बाल गोविंद अकेले रहते थे। लगभग पांच महीने पहले, बाल गोविंद ने अपना टेंपो बेचकर बेटे लवकुश के लिए एक ऑटो खरीदा था। लवकुश प्रतिदिन ऑटो चलाकर रात में उसे अपने पिता के मकान पर खड़ा करता था। शुक्रवार रात करीब नौ बजे लव कुश हमेशा की तरह पिता को खाना देने गया और वापस अपने घर लौट आया। शनिवार सुबह जब लव कुश ऑटो निकालने पहुंचा, तो बाल गोविंद के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला। लवकुश ने कई बार आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। खिड़की से झांकने पर उसने बाल गोविंद को पंखे के हुक से मफलर के सहारे लटका हुआ पाया।तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को नीचे उतारा। पुलिस जांच के दौरान कमरे के अंदर टिफिन में खाना रखा मिला, जिसमें से कुछ खाया गया था। टिफिन के पास शराब की एक बोतल भी मिली। इससे यह आशंका जताई जा रही है कि उन्होंने शराब के नशे में यह कदम उठाया होगा। मृतक के परिवार में पत्नी के अलावा दो विवाहित बेटे और एक विवाहित बेटी हैं। आत्महत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से की सौजन्य मुलाकात, 'बस्तर पंडुम 2026' में किया आमंत्रित

बीएनई

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाले राज्यस्तरीय जनजातीय सांस्कृतिक महोत्सव 'बस्तर पंडुम 2026' में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का आमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री साय ने राष्ट्रपति को बस्तर अंचल की समृद्ध जनजातीय कला, संस्कृति, परंपराओं एवं लोक जीवन से अवगत कराते हुए कहा कि बस्तर पंडुम राज्य की जनजातीय विरासत के संरक्षण, संवर्धन और राष्ट्रीय–अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचार का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यह आयोजन तीन चरणों में आयोजित किया जाएगा, जिसका अंतिम चरण फरवरी 2026 में बस्तर में संपन्न होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने राष्ट्रपति को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रों के समग्र विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, बुनियादी ढांचे के विस्तार एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति से भी अवगत कराया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनजातीय समाज को विकास की मुख्यधारा से जोड़ते हुए उनकी सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित रखने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने जनजातीय संस्कृति से जुड़े इस आयोजन की सराहना करते हुए बस्तर पंडुम 2026 के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दीं। उल्लेखनीय है कि बस्तर पंडुम 2026 के माध्यम से लोकनृत्य, लोकगीत, पारंपरिक वाद्ययंत्र, हस्तशिल्प, जनजातीय व्यंजन, वेशभूषा सहित विभिन्न सांस्कृतिक विधाओं का प्रदर्शन किया जाएगा।

नए साल में घूमने की बना रहे योजना; फ्लाइट कैंसिल हो या सामान खो जाए, आसानी से मिलेगा क्लेम

एजेंसी

नई दिल्ली। नए साल में अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं, तो ट्रैवल इंश्योरेंस जरूर रखें। ट्रैवल इंश्योरेंस का मकसद यात्रा के दौरान आई अचानक परेशानी से आपको सुरक्षित रखना है। हाल ही में परिचालन संबंधी चुनौतियों के कारण दिल्ली, मुंबई, पुणे, बंगलूरू और हैदराबाद सहित कई प्रमुख हवाईअड्डों पर लोगों को फ्लाइट कैंसिलेशन और देरी की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऐसी मुश्किल स्थितियों में ट्रैवल इंश्योरेंस काफी मददगार साबित होता है। अगर आपने कॉम्प्रिहेंसिव ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, तो ऐसे मुश्किल हालात यह समझने का सबसे अच्छा मौका होते हैं कि आपकी कवरेज कब और कैसे काम आ सकती है। अगर आपकी फ्लाइट कैंसिल हो जाए, ट्रांसफर मिस हो जाए, अचानक मेडिकल संबंधी जरूरतें आ जाए या होटल बुकिंग करने में दिक्कत आए, खासकर जब एयरलाइन के परिचालन में इस तरह की गड़बड़ी हो जाए, तब आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत क्लेम किस प्रकार और कब दर्ज करना होता है। यात्रा से पहले की तैयारी यात्रा पर निकलने से पहले यह जरूरी है कि आप साथ ले जाने वाली सभी महंगी और कीमती चीजों की सूची बना लें। पसंदीदा डेस्टिनेशन के लिए रवाना होने से पहले जो भी कीमती सामान या दस्तावेज साथ ले जा रहे हैं, उनकी तस्वीरें खींचकर सुरक्षित रख लें। इसके अलावा, अपने सभी ट्रैवल दस्तावेज की एक कॉपी बना लें और उसे परिवार के भरोसेमंद सदस्य या दोस्त के पास रख दें और असली दस्तावेज को अपने साथ लेकर सफर पर जाएं। ट्रैवल क्लेम अनुभव को आसान बनाने के तरीके शर्तें बारीकी से पढ़ना शर्तों को पढ़ने से यह पता चलता है।

सामुदायिक सहभागिता को सुदृढ़ करने की दिशा में एनटीपीसी सिंगरौली की पहल : ग्राम प्रधानों के साथ परियोजना प्रमुख का संवाद

बीएनई

सिंगरौली। एनटीपीसी सिंगरौली के कार्यकारी निदेशक एवं परियोजना प्रमुख संदीप नायक ने सामुदायिक सहभागिता को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से निकटवर्ती ग्रामों के ग्राम प्रधानों के साथ एक संवादात्मक बैठक आयोजित की। इस बैठक में कोटा ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान प्रमोद तिवारी, चिलकाटांड ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान हीरालाल तथा परसवार राजा ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान अविनाश भारती की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर नायक ने सभी सम्मानित ग्राम प्रधानों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ दीं, एनटीपीसी सिंगरौली को निरंतर मिल रहे उनके सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया तथा क्षेत्रीय विकास एवं जनहित से जुड़े विविध विषयों पर सार्थक एवं गहन विचार–विमर्श किया। उन्होंने विशेष रूप से स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, एनटीपीसी टाउनशिप एवं आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने, सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने, दोपहिया वाहन चालकों द्वारा हेलमेट के अनिवार्य उपयोग, तेज एवं रेस ड्राइविंग की रोकथाम तथा यातायात अनुशासन सुनिश्चित करने हेतु व्यापक जनजागरूकता की आवश्यकता पर बल दिया। नायक ने कहा कि एनटीपीसी सिंगरौली चिलकाटांड, कोटा एवं परसवार राजा ग्रामों में जनसुविधाओं के विस्तार और आधारभूत विकास कार्यों को वृहद स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि ग्राम पंचायतों एवं एनटीपीसी के बीच बेहतर सहयोग और समन्वय से ही सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सतत क्षेत्रीय विकास संभव है। बैठक के दौरान सभी ग्राम प्रधानों ने एनटीपीसी से संबंधित जनसमस्याओं, आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं को रखते हुए सकारात्मक सुझाव दिए तथा भविष्य में निरंतर सहयोग का आश्वासन दिया। इस संवाद बैठक में जोसेफ बास्टियन, मुख्य महाप्रबंधक (प्रचालन एवं अनुरक्षण), रश्मि रंजन मोहंती, महाप्रबंधक (परियोजना) सहित मानव संसाधन विभाग, बीएचईएल एवं नगर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे, जिससे बैठक और अधिक व्यापक एवं परिणामोन्मुखी बन सकी।

मुख्यमंत्री ने किया उत्तराखंड माल्टा महोत्सव का शुभारंभ

राज्य में माल्टा मिशन शुरू करने की घोषणा

दिल्ली में भी आयोजित होगा उत्तराखंड माल्टा महोत्सव – मुख्यमंत्री

बीएनई

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को राजकीय उद्यान सर्किट हाउस गढ़ीकैंट में उत्तराखंड माल्टा महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य में माल्टा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए माल्टा मिशन शुरू करने की घोषणा करते हुए कहा कि दिल्ली में भी राज्य की ओर से माल्टा महोत्सव का आयोजन किया जायेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने अपनी धर्मपत्नी गीता पुष्कर धामी के साथ विभिन्न जनपदों के माल्टा एवं नींबू प्रजाति के फलों की प्रदर्शनी का अवलोकन कर माल्टा एवं नींबू की खटाई सहित नींबू प्रजाति के फलों से बने विभिन्न उत्पादों का स्वाद भी लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि माल्टा उत्तराखंड की पहचान एवं परंपरा से जुड़ा है। राज्य की आर्थिकी व समृद्धि को सशक्त करने में बागवानी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इन्हीं संभावनाओं को साकार करने के लिए राज्य सरकार ने एप्पल मिशन व कीवी मिशन जैसी कई उल्लेखनीय शुरूआत की है। इसी तर्ज पर राज्य में माल्टा के उत्पादन को बढावा देने के लिए माल्टा मिशन की शुरूआत की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के माल्टा की ब्रांडिंग व इसे बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए भी सरकार के द्वारा अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। राज्य के हर जनपद में माल्टा महोत्सव का आयोजन इन्हीं प्रयासों की एक कड़ी है। उन्होंने कहा कि राज्य के माल्टा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए दिल्ली में भी राज्य की ओर से माल्टा महोत्सव का आयोजन किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों की आर्थिकी को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। खेती व बागवानी के क्षेत्र में समुचित प्रोत्साहन, नवाचार और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाई जा रही है। यह पहल पलायन रोकने और युवाओं को अपने गांव के पास ही रोजगार देने में गेम चेंजर साबित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार स्थानीय विशिष्टताओं के अनुरूप उपयुक्त खेती और बागवानी को प्रोत्साहित कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में माल्टा, सेब, नाशपाती, कीवी, अखरोट, आड़ू और नींबू वर्गीय फलों के बागान स्थापित करने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। फसल आधारित क्लस्टर विकसित कर उत्पादन और विपणन को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राज्य में माल्टा व गलगल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। सरकार द्वारा बागान लगाने पर 50 प्रतिशत अनुदान, सूक्ष्म सिंचाई पर 70 से 80 प्रतिशत अनुदान तथा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों पर 60 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। सेलाकुई में सुगंधित पौधों के लिए स्थापित केंद्र का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महक क्रांति की शुरूआत कर राज्य में सुगंधित पौधों की खेती को भी व्यापक स्तर पर बढ़ावा देने की महत्वपूर्ण पहल की गई है। मुख्यमंत्री ने माल्टा महोत्सव में प्रतिभाग करने आए पौड़ी गढ़वाल के माल्टा उत्पादक हरीश के प्रयासों की सराहना करते हुए बताया कि उन्होंने 53 प्रजातियों के लगभग एक हजार पौधे रोपित किए हैं तथा इस बार भी 200 पौधे रोपित करने की तैयारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अन्य किसानों को इनसे प्रेरणा लेकर बागवानी के क्षेत्र में विद्यमान संभावनाओं को साकार करने में सरकार के प्रयासों को सफल बनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि माल्टा जैसे स्थानीय फलों के उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन को बढ़ावा देने से किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के महोत्सव किसानों को नए बाजारों से जोड़ने के साथ–साथ स्वरोजगार के नए अवसर भी प्रदान करते हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि आने वाले पाँच वर्षों में उत्तराखंड औद्यानिकी के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार का निरंतर प्रयास है कि माल्टा जैसे स्थानीय फलों के उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन को प्रोत्साहित कर इसका सीधा लाभ प्रदेश के किसान भाइयों तक पहुँचाया जाए और यह महोत्सव इन्हीं प्रयासों का सशक्त प्रमाण है। कार्यक्रम में सांसद नरेश बंसल, विधायक सविता कपूर, दायित्वधारी कैलाश पंत, प्रताप सिंह पंवार तथा सचिव कृषि डॉ. एस.एन. पाण्डेय सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं विभिन्न जनपदों से आए किसान भी उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़ की अद्भुत लोक नृत्य एवं लोककला को जीवित रखना फोटो प्रदर्शनी का उद्देश्य

बीएनई

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में लोक कला अत्यंत सुंदर अद्भुत है क्लाउड द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य की लोक नृत्य एवं लोक कला को जन–जन तक पहुंचना है । आज प्रदर्शनी में भानु प्रतापपुर बस्तर क्षेत्र के छात्र–छात्राएं इस कार्यक्रम में आकर बस्तर की सुंदर कला को देख अपने आप को बोलने से नहीं रोक पाए की आमचो बस्तर सुघर बस्तर इसी प्रकार हर वर्ग आयु के लोगों ने फोटो प्रदर्शनी में न सिर्फ भाग लिया बल्कि फोटो प्रदर्शनी की फोटो खींचकर रील बनाकर सोशल मीडिया में शेयर की इस आयोजन से आने युवा पीढ़ी को छत्तीसगढ़ की अद्भुत लोक नृत्य एवं लोककला को जीवित रखना और उसे विश्व पटल पर आगे बढ़ाने की दिशा में एक अवसर है कार्यक्रम के आयोजन के पीछे दीपेंद्र दीवान की सोच थी हमारे राज्य की सुंदर संस्कृति को जन–जन तक न सिर्फ पहुंचना है । इस कार्यक्रम के अवलोकन के लिए कई गणमान्य नागरिक शामिल हुए जिनमें रेलवे के वाणिज्यिक अधिकारी राकेश सिंह वरिष्ठ पत्रकार सरिता दुबे, कुलदीप शुक्ला, नोकिया एवं टाटा कंसलटेंसी से कॉर्पोरेट की टीम ने इस प्रदर्शनी को अत्यंत सराहा इस अवसर पर मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से आई दीपिका मिश्रा जो पूर्व में रायपुर निवासी रही है अब वह ऑस्ट्रेलिया सिटीजनशिप ले चुकी है उन्होंने इस प्रदर्शनी में आकर छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया कहां उन्होंने बताया वह अपनी मिट्टी की खुशबू को बहुत याद करती हैं इस अवसर पर धनलक्ष्मी मिश्रा कॉलेज प्राध्यापिका ने बताया कि यह युवा पीढ़ी के लिए अत्यंत उपयोगी प्रदर्शनी है। इस फोटो प्रदर्शनी में दीपेंद्र दीवान, अखिलेश भरोस, धनेश्वर साहू, हर्षा सिंदूर एवं शौर्य दीवान के फोटोग्राफ्स फोटो प्रदर्शनी में प्रदर्शित हुए हैं इस कार्यक्रम में दीपेंद्र दीवान का कहना है की ऐसे आयोजन निरंतर होते रहना चाहिए जिससे आने वाली पीढियां कोछत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति के झलक देखने को मिलती है यह फोटो प्रदर्शनी छायाचित्रों के माध्यम से न केवल दृश्य सौंदर्य प्रस्तुत करेगी, बल्कि छत्तीसगढ़ के लोक जीवन, सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं के संरक्षण का संदेश भी देगी। प्रदर्शनी का उद्देश्य नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ना, लोक कलाकारों और शिल्पकारों के योगदान को रेखांकित करना तथा लोक कला के प्रति जन–जागरूकता बढ़ाना है। इस कार्यक्रम में अन्य प्रदेशों एवं राज्य के अन्य जिलों से आए लोगों को छत्तीसगढ़ की विविधता अत्यंत पसंद आई कार्यक्रम में बिलासपुर से पीएचडी कर रहे छात्रों का समूह इस कार्यक्रम में शामिल होने आया उन्होंने कार्यक्रम को अत्यंत सराहा कई पर्यटन से जुड़े उद्यमी कार्यक्रम में रोजगार के अवसर को देखने के उद्देश्य से भी शामिल हुए यह आयोजन कला प्रेमियों के साथ–साथ विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं, संस्कृति अध्येताओं और आम नागरिकों के लिए भी छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत को जानने, समझने और अनुभव करने का एक महत्वपूर्ण अवसर सिद्ध होगा। यह

आयोजन 04 जनवरी 2026 तक कला वीथिका, महंत घासीदास परिसर, घड़ी चौक, रायपुर में आयोजित की जा रहीं है स प्रदर्शनी में प्रवेश सभी के लिए पूर्णतः निःशुल्क है और प्रदर्शनी सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेगी, जिससे अधिक से अधिक लोग इस सांस्कृतिक आयोजन से जुड़ सकें।

विजय देवरकोंडा की 'किंगडम' पर नागा वामसी ने दी बड़ी अपडेट, निर्माता ने बताया फिल्म बनेगी या नहीं

एजेंसी

अभिनेता विजय देवरकोंडा इन दिनों अपनी शादी और आगामी फिल्म श्राउडी जनार्धना' को लेकर चर्चाओं में हैं। हालांकि, इस बीच फैंस ये भी जानना चाहते हैं कि उनकी फिल्म 'किंगडम' के दूसरे पार्ट को लेकर क्या अपडेट है। अब फिल्म के प्रोड्यूसर नागा वामसी ने 'किंगडम' के सीक्वल को लेकर बड़ी अपडेट दी है। जानिए उन्होंने क्या बताया... नहीं बन रहा 'किंगडम' का सीक्वल आइडलब्रेन साथ हालिया बातचीत में फिल्म के निर्माता नागा वामसी ने 'किंगडम' के सीक्वल को लेकर स्पष्ट किया कि फिलहाल यह फिल्म रद्द हो गई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नहीं, अब हम इसे नहीं बना रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या यह फिल्म एक ही फिल्म के रूप में बेहतर प्रदर्शन कर सकती थी, बजाय इसके कि इसे सीक्वल के रूप में पेश किया जाए? इस पर उन्होंने जवाब दिया कि जो हुआ उसके बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि इससे केवल निर्देशक गौतम तिन्नानुरी को ही दुख होगा। अब करने के लिए कुछ नहीं बचा है। हालांकि, उन्होंने कहा कि वो जल्द ही निर्देशक गौतम तिन्नानुरी के साथ दोबारा काम करेंगे। गौतम गौतम अब एक अलग तरह की फिल्म पर काम कर रहे हैं। बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हुई थी 'किंगडम' 'किंगडम' पिछले साल जुलाई में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। उस समय विजय को अपने करियर को फिर से पटरी पर लाने के लिए एक हिट फिल्म की सख्त जरूरत थी, जो 2022 में आई फिल्म 'लाइगर' की रिलीज के बाद से गिरावट की ओर जा रहा है। लेकिन 'किंगडम' भी बॉक्स ऑफिस पर कोई खास प्रदर्शन नहीं कर सकी।

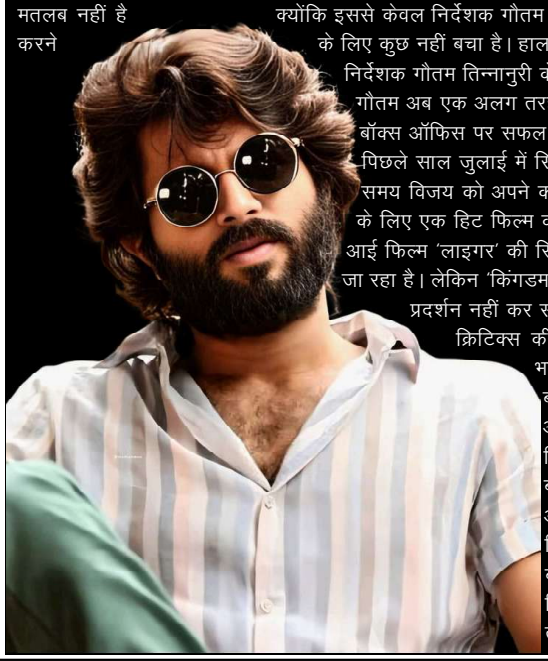

क्रिटिक्स की मिली–जुली प्रतिक्रिया के बाद भारी भरकम बजट में बनी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड के आंकड़े को भी नहीं छू पाई। इस फिल्म में सत्यदेव, वेंकटेश और भाग्यश्री बोरसे भी अहम भूमिकाओं में नजर आए थे। विजय ने सूरी का किरदार निभाया है, जो एक कांस्टेबल से जासूस बन जाता है और श्रीलंका में एक गिरोह में घुसपैठ करने के लिए खुफिया तौर पर भेजा जाता है।

संक्षिप्त

आईएसएल निलंबन के मामले पर सामने आए छेत्री सहित अन्य फुटबॉल खिलाड़ी, फीफा से की हस्तक्षेप की मांग

एजेंसी

नई दिल्ली। सुनील छेत्री सहित भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ियों और इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) में खेलने वाले कई विदेशी खिलाड़ियों नेफुटबॉल की वैश्विक संस्था फीफा से आईएसएल के निलंबन पर हस्तक्षेप की अपील की। अभी तक आईएसएल का 2025–26 सत्र शुरू नहीं हो पाया है। ऐसे में सीनियर राष्ट्रीय टीम के खिलाड़ी छेत्री, गुरप्रीत सिंह संधू और संदेश झिंगन ने लंबे समय से बनी अनिश्चितता पर चिंता जताते हुए चेतावनी दी कि भारतीय फुटबॉल स्थायी ठहराव की स्थिति में पहुंच रहा है। खिलाड़ी बोले– एआईएफएफ जिम्मेदारी निभाने की स्थिति में नहीं खिलाड़ियों ने कहा कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) अब अपनी जिम्मेदारियां निभाने की स्थिति में नहीं है और उन्होंने देश में खेल के भविष्य की रक्षा के लिए फीफा से आगे आने की अपील की। गुरप्रीत ने सोशल मीडिया पर साझा किए गए संयुक्त वीडियो बयान में कहा, श्जनवरी का महीना है और हमें इस वक्त आईएसएल के प्रतिस्पर्धी फुटबॉल मैचों में आपकी स्क्रीन पर होना चाहिए था।श झिंगन ने जोड़ा, इसके बजाय हम डर और बेबसी के चलते वह बात कहने को मजबूर हैं, जिसे हम सभी जानते हैं। अन्य खिलाड़ियों ने कहा, सबसे अहम बात यह है कि हम एक गुहार लगाने आए हैं। भारतीय फुटबॉल का प्रशासन अब अपनी जिम्मेदारियां निभाने में सक्षम नहीं है। हम अब स्थायी ठहराव की ओर हैं। जो कुछ बचाया जा सकता है, उसे बचाने की यह आखरिी कोशिश है। इसलिए हम फीफा से अनुरोध कर रहे हैं कि वह आगे आए और भारतीय फुटबॉल को बचाने के लिए जो जरूरी हो, वह करे।श छेत्री ने निष्कर्ष में कहा, खिलाड़ी, स्टाफ, मालिक और प्रशंसक सभी स्पष्टता, सुरक्षा और सबसे बढ़कर एक भविष्य के हकदार हैं। क्यों अब तक शुरू नहीं हुआ आईएसएल का सत्र? आईएसएल के 2025–26 सत्र को जुलाई में इसलिए रोक दिया गया था क्योंकि लीग के पूर्व आयोजक फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड (एफएसडीएल) और एआईएफएफ के बीच मास्टर राइट्स एग्रीमेंट (एमआरए) के नवीनीकरण को लेकर अनिश्चितता बनी हुई थी। यह समझौता आठ दिसंबर को समाप्त हो गया।

सिडनी में पांचवें एशेज टेस्ट के लिए सुरक्षा कड़ी, बॉन्डी बीच गोलीबारी कांड को देखते हुए लिया फैसला

एजेंसी

नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच रविवार से सिडनी में एशेज सीरीज का पांचवां और अंतिम टेस्ट मैच खेला जाएगा। इस मुकाबले से पहले सिडनी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सिडनी में बॉन्डी बीच गोलीबारी कांड को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। इस मैच के दौरान लंबी राइफलों से लैस पुलिस गश्त करेगी। ऑस्ट्रेलिया में किसी खेल प्रतियोगिता के दौरान अमूमन इस तरह की सुरक्षा नहीं देखी जाती है। स्टेडियम खचाखच भरे रहने की संभावना सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (एससीजी) में होने वाले इस मैच में स्टेडियम खचाखच भरे रहने की संभावना है। इस दौरान वर्दीधारी और घुड़सवार पुलिस के साथ–साथ सार्वजनिक व्यवस्था और दंगा नियंत्रण दस्ते के अधिकारी भी निगरानी रखेंगे। बॉन्डी बीच में तीन सप्ताह पहले हनुक्का उत्सव के दौरान दो बंदूकधारियों ने 15 लोगों की हत्या कर दी थी।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक **धर्मेन्द्र सिंह** द्वारा शौर्य प्रिंटर्स, शिवपुरी कालोनी, निकट बांसमण्डी चौराहा, लखनऊ से मुद्रित तथा एमआईजी-47, सेक्टर-ई, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.) से प्रकाशित
सम्पादक-अंजू सिंह (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा) Email-lkojunction@gmail.com. RNI NO.-UPHIN/2015/64743